उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा एवं सतत विकास

*डॉ. मीना सिरोला
**हिमाद्रि विश्नोई

सारांश

विद्यालयी शिक्षा का वर्णन वैदिक भारत के आदिम साहित्य में मिलता है। भारत में विद्यालयी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र मंदिर और गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में समय के साथ–साथ विद्यालयी शिक्षा का द्रुत गति से विकास हुआ। विद्यालयी शिक्षा समाज के विकास के साथ–साथ राष्ट्र के आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन भारत ने वैदिक युग से ही उच्च कोटि की शिक्षा के महत्व को महसूस किया था लेकिन आक्रमण और विदेशी हमलों के साथ वैदिक कालीन गुरुकुल तथा मंदिरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा की पारंपरिक नींव नष्ट हो गई। ब्रिटिश शासन के भारत में आने के बाद भारत की विद्यालयी शिक्षा का स्वरुप पूरी तरह से परिवर्ती हो चूका था। अंग्रेजों ने भारत में विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने की पहल की, लेकिन इसका पारंपरिक विद्यालयी शिक्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। पारंपरिक स्वदेशी प्रणाली को भारी नुकसान हुआ क्योंकि जो नई प्रणाली शुरू की गई थी उससे समाज के केवल उस वर्ग को लाभ हुआ जो अंग्रेजी सरकार की सेवा करता था।

उत्तराखण्ड राज्य में 22 सितम्बर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुयी। प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.63 (8. 01प्रतिशत की वृद्धि) प्रतिशत हो गई परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वे स्थान से खिसककर कर 17वे स्थान पर आ गया है। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की रिपोर्ट प्रगति प्रतिवेदन 2020–21 ''विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड का शैक्षिक परिदृश्य/शैक्षिक सांख्यिकी'' के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल 11,653 प्राथमिक विद्यालय तथा 2608 माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में क्रियाशील हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडिया दिनांकित 2 दिसंबर 2022 के एक आलेख के अनुसार उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा में 11.5 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

यह शोध पत्र उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालयों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या पर चर्चा करता है। यह शोध पत्र उत्तराखंड राज्य में विद्यालयी शिक्षा के सतत विकास तथा सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल के प्रमुख लक्ष्यों पर प्रकाश डालता है तथा विद्यालयी शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में सुझावों पर चर्चा करता है।

मुख्य शब्द : विद्यालयी शिक्षा, सतत विकास, विद्यार्थी नामांकन, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल के प्रमुख लक्ष्य

परिचयः उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा

उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित 27वां राज्य है, जो 53,483 वर्ग किमी में फैला है; यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक अद्वितीय भौगोलिक इकाई है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सीमा 200 से 7784 मीटर है। राज्य का 86 प्रतिशत भाग पहाड़ी है और 65 प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। राज्य पूर्व में नेपाल और उत्तर में

चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भी साझा करता है। राज्य में दो प्रशासनिक ब्लॉक हैं जो राज्य को कुमाऊं और गढ़वाल नामक दो भागों में विभाजित करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में 6 जिले हैं, अर्थात् नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोडा, पिथौरागढ, बागेश्वर और चंपावत, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में 7 जिले हैं, अर्थात् उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग, चमोली, हरिद्वार और पौडी। राज्य के 13 जिलों में से 3 मैदानी जिले हैं और शेष 10 पहाड़ी जिले हैं।

9 फरवरी 1996 को उत्तराखण्ड क्षेत्र हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जिले की तहसील रामनगर में हुयी। इस कार्यालय द्वारा प्रथम बार सन् 1999 में गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल हेतु बोर्ड (परिषदीय) परीक्षाओं का संचालन कराने का भार उठाया गया तथा राज्य के गठन के बाद फिर वर्ष 2001 में गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डलों हेतु बोर्ड (परिषदीय) परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय रामनगर द्वारा संचालित की गयीं। उत्तराखण्ड राज्य में 22 सितम्बर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुयी। वर्ष 2002 में रामनगर परिषद द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रथम बार परीक्षाओं का स्वतंत्र आयोजन किया गया। 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2006 का प्राख्यापन (issuance) हुआ तथा उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद की स्थापना हुयी। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 201/XXIV-5/2008 देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद का गठन हुआ।

प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर वर्ष की जनगणना के अनुसार 71.62 प्रतिशत थी। प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2001 में बढ़कर 79.63 (8.01 प्रतिशत की वृद्धि) प्रतिशत हो गई परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वे स्थान से खिसककर कर 17वे स्थान पर आ गया है। सम्पूर्ण भारत के औसत 74.04 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य का साक्षरता प्रतिशत 79.63 है। 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि उत्तराखण्ड में, पुरुष व महिला की साक्षरता क्रमशः 88.33 प्रतिशत और 70.70 प्रतिशत है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया दिनांकित 2 दिसंबर 2022 के एक आलेख के अनुसार उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा में 11.5 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

- उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा का निम्न के संदर्भ में अध्ययन करनाः
    - विद्यार्थियों का नामांकन
    - विद्यार्थियों की संख्या
    - विद्यालयों की संख्या
    - शिक्षकों की संख्या
- उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा के सतत विकास तथा सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल के प्रमुख लक्ष्यों का अध्ययन करना।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

पांडेय, ठाकुर देव तथा पाठक, ज्योति (2018) में शोध पत्र 'हायर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड' में पर्वतीय जिलों में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन प्रतिशत पर चर्चा की गई और पाया गया कि कुल

आबादी का केवल 1.59 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा में नामांकित है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता की कमी भी राज्य में एक बड़ी समस्या है। अधिकांश कॉलेज दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं और खराब कनेक्टिविटी के कारण शिक्षण में उन्नत तकनीकों का उपयोग लोकप्रिय नहीं है, गुणवत्ता अनुसंधान आउटपुट की कमी कई समस्याओं में से एक है जो राज्य में खराब उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे का परिणाम है। उच्च शिक्षा के माध्यम से सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सतत विकास प्रक्रिया को संचालित करने वाली कई गुणवत्ताएँ उच्च शिक्षा के माध्यम से ही आती हैं।

पी.डी., सिंह; मन्हास, ए. एस. तथा गुसैन, एस. (2020) में अपने शोध पत्र 'क़्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पौड़ी गढ़वाल' में पाया की यद्यपि छात्र–शिक्षक अनुपात में कमी आई है और शुद्ध नामांकन अनुपात में उतार–चढ़ाव है. लेकिन पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों की वृद्धि हुई है और ड्रॉपआउट दर में कमी आई है. जिससे जिला पौडी गढ़वाल सबसे अधिक सीखने वाले जिलों में से एक बन गया है। नीति आयोग द्वारा आयोजित एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 के अनुसार एसडीजी लक्ष्य 4 सूचकांक में उत्तराखंड को 9वें स्थान पर रखा गया है।

भट्ट, व्योमकेश (2020) ने शोधपत्र 'ए स्टडी ऑफ़ थे डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन उत्तराखंड एंड इट्स चैलेंजेज' में पाया की उत्तराखंड में समय के साथ स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है। उच्च शिक्षा में पहाड़ी क्षेत्रों में नामांकन का स्तर कम है जबकि शहरी क्षेत्रों में नामांकन का स्तर अच्छा था। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च संस्थानों की संख्या भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है।

सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एंड गुड गवर्नेंस,डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ उत्तराखंड, कपंडियम (रिपोर्ट 2021) 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन उत्तराखंड' अध्याय 8 शीर्षक 'इन्नोवेशंस स्ट्रेंग्थेनिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द स्टेट थ्रू इ– लर्निंग' की केस स्टडी में प्रोजेक्ट एडुहिल को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने वाली नवीन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के 13वें वित्त आयोग के तहत जिला नवाचार निधि के तहत एक परियोजना प्रदान की गई है। एडवेल ने शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के सहयोग से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक के दो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में इस परियोजना को क्रियान्वित किया। कार्यक्रम पूर्व सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 5वीं तक के 90 प्रतिशत से अधिक छात्र अंग्रेजी में अपना नाम और 4 से 6 शब्दों का एक सरल वाक्य लिखने में सक्षम नहीं थे। ग्रामीण उत्तराखंड के गैर प्रोजेक्ट स्कूलों के 30 प्रतिशत छात्रों की तुलना में प्रोजेक्ट में कक्षा 5वीं के छात्र 83 प्रतिशत आसान वाक्य पढ़ सकते हैं।

भारती तथा बिष्ट, पदम् सिंह (2022) ने अपने शोध पत्र 'एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन सेक्टर इन द उत्तराखंड स्टेट' में पाया की राज्य में संस्थानों और नामांकनों की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी जा रही है।

उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा के स्तर और लिंग के आधार पर नामांकन

यू डायस 2021–2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में पूर्व प्राथमिक स्तर पर कुल विद्यार्थी 9495207 नामांकित हुए जिसमें से 5051523 बालक तथा 4443684 बालिकाएं थी। प्राथमिक स्तर पर कुल 121842250 विद्यार्थी नामांकित हुए जिसमें से 63517655 बालक 38324595 बालिकाएं थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 66790692 विद्यार्थी नामांकित हुए जिनमें से 34511750 बालक तथा 32278942 बालिकाएं थी। माध्यमिक स्तर पर कुल 38528631 विद्यार्थी नामांकित हुए जिसमें 20071918 बालक तथा 18456713 बालिकाएं थी। उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 28579050 विद्यार्थी नामांकित हुए जिसमें से 14747732 बालक 13831318 बालिकाएं थी।

उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा के स्तर और लिंग के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 2021–2022

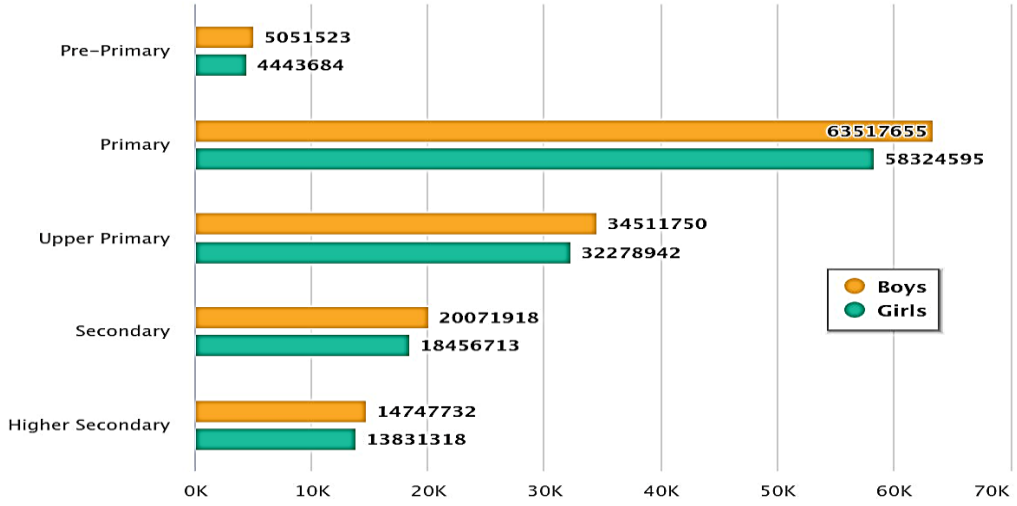

चित्र.1: शिक्षा के स्तर और लिंग के आधार पर बालक तथा बालिका नामांकन (स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

तालिका.1: उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के स्तर और लिंग के आधार पर बालक तथा बालिका नामांकन (2021–2022)

वर्ग	बालक	बालिकाएं	कुल
पूर्व प्राथमिक	5051523	4443684	9495207
प्राथमिक	63517655	58324595	121842250
उच्च प्राथमिक	34511750	32278942	66790692
माध्यमिक	20071918	18456713	38528631
उच्च माध्यमिक	14747732	13831318	28579050

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्याः

यू डायस 2021–2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में विद्यालयी शिक्षा में कुल 264527575 विद्यार्थी हैं। जिसमें से 980808 (40 प्रतिशत) विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में हैं। 156815 (6.4 प्रतिशत) विद्यार्थी एडेड विद्यालयों में, 1238714 (50.6 प्रतिशत) विद्यार्थी निजी विद्यालयों में तथा 73589 (3.0 प्रतिशत) विद्यार्थी अन्य विद्यालयों में हैं।

चित्र.2: उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या (2021–2022) प्रतिशत में

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

तालिका.2: उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या (2021–2022)

वर्ग	छात्रों की कुल संख्या	प्रतिशत
सरकारी	980808	40
एडेड	156815	6.4
निजी	1238714	50.6
अन्य	73589	3.0

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

उत्तराखंड राज्य में विद्यालयों की संख्या:

यू डायस 2021–2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल 1507708 विद्यालय हैं, जिनमें से 1032570 (72.3 प्रतिशत) सरकारी विद्यालय, 84362 (2.7 प्रतिशत) एडेड विद्यालय तथा 337499 (22.9 प्रतिशत)निजी विद्यालय हैं। 53277 (2.2 प्रतिशत) अन्य विद्यालय हैं।

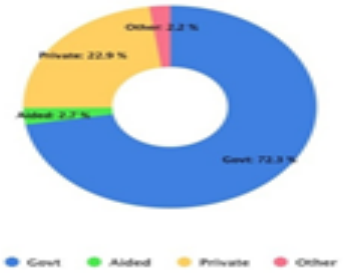

चित्र.3: उत्तराखंड राज्य में विद्यालयों की संख्या (2021–2022) प्रतिशत में

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

तालिका.3: उत्तराखंड राज्य में विद्यालयों की संख्या (2021–2022) प्रतिशत में

वर्ग	स्कूलों की कुल संख्या	प्रतिशत
सरकारी	1032570	72.3
एडेड	84362	2.7
थ्नजी	337499	22.9
अन्य	53277	2.2

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों की संख्या :

यू डायस 2021–2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षकों की कुल संख्या 9687577 है। जिसमें से 4938868 (48.2 प्रतिशत) शिक्षक सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। 820301 (4.2 प्रतिशत) शिक्षक एडेड विद्यालयों में, 3602625 (45.7 प्रतिशत) शिक्षक निजी विद्यालयों में तथा 325783 (1.9 प्रतिशत) शिक्षक अन्य विद्यालयों में पढ़ाते हैं।

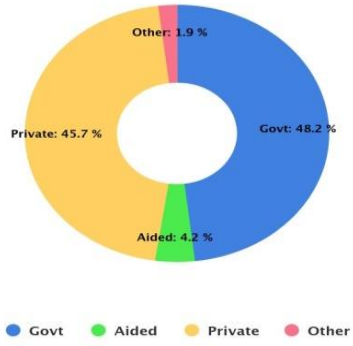

चित्र.4: उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों की संख्या (2021–2022) प्रतिशत में

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

तालिका.4: उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों की संख्या (2021–2022) प्रतिशत में

वर्ग	शिक्षकों की कुल संख्या	प्रतिशत
सरकारी	4938868	48.2
एडेड	820301	4.2
निजी	3602625	45.7
अन्य	325783	1.9

(स्त्रोतः यू डायस रिपोर्ट 2021–2022)

सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल के प्रमुख लक्ष्यः

इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलेपमेंट (2018) की रिपोर्ट 'SDG4 एनश्योर इंक्लूसिव एंड इकविटेबल क़्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफलॉन्ग लर्निंग अपोरच्युनीटीस फॉर आलः उत्तराखंड विज़न 2030' के अनुसार सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल (एसडीजी 4) के प्रमुख लक्ष्य हैं कि सभी बालक तथा बालिकाओं को मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो। लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विकलांगता, जातीयता या अन्य कारकों के बावजूद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक कौशल वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करना। व्यक्तियों को कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल (एसडीजी 4) का लक्ष्य उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में 2030 तक सभी के लिए समावेशी, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर सुनिश्चित करना है।

उत्तराखंड राज्य विद्यालयी शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में सुझावः

- शिक्षा के सभी स्तरो पर लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास करना बहुत ज़रूरी है।
- मूलभूत कौशल पर ध्यान देने के साथ, बच्चों और वयस्कों के बीच साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार करना आवश्यक है।
- समावेशी और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन के लिए योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है।
- सतत विकास, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता की सराहना के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से शिक्षा प्रणालियों के निर्माण और मजबूती में के लिए छात्रवृत्ति और सहायता का विस्तार करना आवश्यक है ।

निष्कर्षः

यू डायस 2021–2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा में शुद्ध नामांकन अनुपात 89. 18 प्रतिशत (प्राथमिक) और 71 प्रतिशत (उच्च प्राथमिक स्तर) पर उच्च है। माध्यमिक स्तर में शुद्ध नामांकन अनुपात बहुत कम मात्र 51.28 प्रतिशत है। शिक्षा की गुणवत्ता राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्कूल–पूर्व शिक्षा पर्याप्त नहीं है, 10 से कम छात्रों वाले 2000 स्कूलों में शिक्षक तैनाती को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। पहाड़ी इलाकों में शिक्षा वितरण की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक है और राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सेवा वितरण की लागत राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वोकेशनल स्ट्रीम में कम बजट प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लिंग समानता सूचकांक क्रमशः 0.89 और 0.92 हैं। सतत विकास, गरीबी में कमी, बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और शांति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए पहुंच, समावेशिता और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

*आचार्य
**शोधार्थी
शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई (राज.)

सन्दर्भः

- भारती; बिष्ट, पदम् सिंह (2022). एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन सेक्टर इन द उत्तराखंड स्टेट *इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च, 4* (3),1–7. https://www.ijfmr.com/papers/2022/3/3821.pdf
- भट्ट, व्योमकेश (2020). 'ए स्टडी ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन उत्तराखंड एंड इट्स चैलेंजेज'. *शिक्षण संशोधन जर्नल ऑफ़ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज,3* (6),37–42. https://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/wp-content/uploads/SS202006009.pdf
- इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलेपमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ उत्तराखंड. (2018). *SDG4 उत्तराखंड विज़न 2030: एनश्योर इंक्लूसिव एंड इकविटेबल क़्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफलॉन्ग लर्निंग अपोरच्युनीटीस फॉर आल* . Retrieved from https://www.ihdindia.org/pdf/Uttarakhand_Vision_2030.pdf
- पांडेय, ठाकुर देव; पाठक, ज्योति (2018). हायर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड. *रिसर्च रिव्यु इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसीप्लीनरी, **03*** (03),79–83. *https://www.academia.edu/39598307/Higher_Education_and_Sustainable_Development_in_Uttarakhand*
- पी.डी., सिंह; मन्हास, ए. एस.; गुसैन, एस. (2020). क़्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पौड़ी गढ़वाल.*हिमालयन जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, 15* (2020),19–30. DOI: **https://doi.org/10.51220/hjssh.v15i1.3**
- सिंह, अमितेन्द्र; उपाध्याय दीनदयाल. *आधुनिक उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था.* हल्द्वानीः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय. https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MAHI-506.pdf
- त्यागी, तन्मय (2022,दिसम्बर 2). उत्तराखंडः स्कूल्ज विथ फ्यूअर स्टूडेंट्स टू बी मर्ज्ड विथ बिग वंस. *टाइम्स ऑफ़ इंडिया.* *https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/uttarakhand-schools-with-fewer-students-to-be-merged-with-big-ones/articleshow/95925624.cms*
- यू डायस रिपोर्ट (2021–2022).Retrieved from-https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/state
- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (2020–21). *विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड का शैक्षिक परिदृश्य– शैक्षिक सांख्यिकी– साभार– प्रगति प्रतिवेदन 2020–21.* Retrived from https://schooleducation.uk.gov.in/files/PRIMARY_AND_UPPER_PRIMARY.pdf https://schooleducation.uk.gov.in/files/MADHYMIK_SCHOOLS.pdf
- यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एंड गुड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ उत्तराखंड.(2021). *सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन उत्तराखंडः इन्नोवेशंस स्ट्रेंथेनिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द स्टेट थ्रू इ– लर्निंग.* Retrieved from http://cppgg.uk.gov.in/wp-content/uploads/2020/09/SDG-Uttarakhand-Compendium.pdf